

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शनिवार, 19 दिसम्बर, 1987/ 28 अग्रहायण, 1909

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1987

सं० डी०एल०आर०-19/87.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि हिमाचल प्रदेश सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट, 1972 (1973 का 19)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा,

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972

(1973 का 19)

(10 जुलाई, 1973)

(1-9-87 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश राज्य में भू-जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अनियमित हो :—

### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 है। संक्षिप्त नाम,  
विस्तार  
और  
प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।
- (3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।
2. एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य नीति को प्रभावशील बनाने के लिए है। राज्य नीति  
के कतिपय  
निदेशक  
सिद्धांतों को  
प्रभावी  
बनाने के  
लिये  
घोषणा।
3. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) “वयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवयस्क नहीं है;
  - (ख) “नियत दिन” से जनवरी 1971 का चौबीसवां दिन अभिप्रेत है;
  - (ग) “बंजर भूमि” से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नियत दिन से तुरन्त पूर्ववर्ती दो वर्ष से अन्यून लगातार अवधि के लिए अकृष्ट रही है और इसक अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में बंजर भूमि के रूप में अभिलिखित कृषि योग्य बंजर भूमि है;
  - (घ) “कुलैक्टर” से जिले का कुलैक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कुलैक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो;
  - (ङ) “कुटुम्ब” से पति, पत्नी और उनकी अवयस्क सन्तान या उनमें से कोई एक या अधिक अभिप्रेत है;

(डड) “विकलांग व्यक्ति” से अंग, या शारीरिक या चिकित्सक दृष्ट्या से लुप्तपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है और जो क्षति, बिमारी या जन्मजात अंगविकार के कारण सामान्य जीवन व्यतीत करने से या उस काम के लिए जिसमें वह नियोजित है पूरी मजदूरी उपाजित करने या नियोजन उपाप्त करने या बनाए रखने से या उस क्षति, बिमारी या अंगविकार के कारण ऐसे काम का भार अपने ऊपर लेने से जो उसकी आयु, अनुभव और अर्हताओं के अनुकूल होता, सारभूत रूप से निवारित या असमर्थ है;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति जिसकी निर्धोग्यता पचास प्रतिशत की सीमा तक या उससे अधिक है, सारभूत रूप से असमर्थ या निर्धोग्य व्यक्ति समझा जायेगा” ।

(डडड) “घरहीन व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास अपना घर या घर बनाने के लिए स्थान नहीं है ;

(च) “भूमि” से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगर या ग्राम में किसी भवन के स्थल के रूप में अधिभोग में नहीं है और जो कृषि प्रयोजनों के लिए या कृषि अनुसेवी प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत हैं:—

- (1) ऐसी भूमि पर भवन और अन्य संरचनाओं के स्थल,
- (2) फलोद्यान ,
- (3) घासनियां ,
- (4) बंजर भूमि, और
- (5) निजी वन ;

(छ) “भू-स्वामी” से यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) में इस रूप में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भू-स्वामी का हित-पूर्वाधिकारी या उत्तराधिकारी होगा ;

(ज) “भूमिहीन व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास चाहे स्वामी या अधि-धाता के रूप में कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि नहीं है, मुख्यतः भूमि पर शारीरिक श्रम से जीविका कमाता है और कृषि-व्यवसाय अपनाने का इरादा रखता है और व्यक्तिगत रूप से खेती करने योग्य है ;

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसका पिता जीवित है या जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,000 रुपये से अधिक है, भूमिहीन व्यक्ति नहीं समझा जायेगा ।

(झ) “भू-राजस्व” से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निर्धारित या, यथा स्थिति, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन निर्धारित भू-राजस्व अभिप्रेत है ;

(ञ) “अवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(ट) “फलोद्यान” से भूमि का ऐसा संहत क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर फलदायी वृक्ष ऐसी संख्या में उगाए गए हों कि वे ऐसी भूमि के पर्याप्त भाग को किसी



कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने में प्रचारित करने हों या जब वे पूर्णतः उग जायेंगे, प्रचारित करेंगे, किन्तु इसके अन्तर्गत केले या अमरुद के उद्यान या दाख बाटिका नहीं होगी ;

(ट) "अन्य पात्र व्यक्ति" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

- (i) जिसके पास, चाहे स्वामी या अभिदाता के रूप में कृषि के प्रयोजनों के लिए एक एकड़ से कम भूमि है, मुख्यतः भूमि पर आजीवनिक श्रम से जीविका कमाता है और कृषि व्यवसाय अपनाते का इरादा रखता है और व्यक्तिगत रूप से खेती करने योग्य है ;
- (ii) जिसका पिता जीवित नहीं है, और
- (iii) जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3000 रुपये से अधिक नहीं है:

परन्तु इसके अन्तर्गत, दो या उससे अधिक व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में या खेती की जा रही सम्पदा में हिस्सा या भाग धारण करने वाला व्यक्ति, नहीं होगा।

- (ड) "अनुज्ञेय क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट भूमि का विस्तार अभिप्रेत है ;
- (ढ) "व्यक्ति" से भू-स्वामी (अभिधारी और संकटज्ञा बन्धकदार) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कम्पनी, कुटुम्ब, व्यष्टियों का संगम या अन्य निकाय, चाहे निर्गमित हो या नहीं, और सम्पत्ति धारण करने के लिए समर्थ कोई संस्था है ;
- (ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (त) "निजी वन" से ऐसा वन अभिप्रेत है जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जिस पर राज्य का साम्प्रतिक अधिकार नहीं है या जिसकी सम्पूर्ण वन-उपज या किसी भाग का, राज्य अधिकारी नहीं है ;
- (थ) "पृथक इकाई" से वयस्क पुत्र या उसकी मृत्यु की दशा में, उसकी विधवा और सन्तान, दि कोई हो अभिप्रेत है ;
- (द) "अधिशेष क्षेत्र" से अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (ध) "चाय सम्पदा" से चाय बागान के अधीन क्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत चाय बागान के अनुसूची प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जो विहित किए जाएं ;
- (न) "अभिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भू-स्वामी के अधीन भूमि धारण करता है, और उस भूमि के लिए, उस भू-स्वामी को लगान संदत्त करने का दायी है ; या प्रतिकूल संविदा के कारण दायी होगा, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं:—

- (1) अनु-अभिधारी ; और
- (2) यथास्थिति, अभिधारी या अनु-अभिधारी के हित के पूर्वाधिकारी या उत्तराधिकारी, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:—

- (क) भू-स्वामी के अधिकारों का बन्धकदार, या
- (ख) कोई व्यक्ति जिसे, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन, यथास्थिति, भू-राजस्व की बकाया या ऐसी बकाया के रूप में वसूलीय राशि की वसूली के लिए कोई जोत अन्तर्गत की गई है या कोई सम्पदा या जोत पट्टे पर दी गई है।

(ग) X X X X X X

- (ग) "अभिधृति" से भू-स्वामी के अभिधारी द्वारा एक पट्टे या समान शर्तों के अधीन धारण किया गया भू-खण्ड अभिप्रेत है, और
- (फ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट 1887 (1887 का 17) में उनके हैं।

अनुज्ञेय क्षेत्र।

4. (1) भू-स्वामी या अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार या अंशतः एक हैसियत में या अंशतः अन्य हैसियत में, व्यक्ति या कुटुम्ब का, जो पति-पत्नी और तीन अवयस्क संतानों से मिलकर बनता है, अनुज्ञेय क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

- (क) सुनिश्चित सिंचाई के अधीन भूमि की दशा में, जो एक वर्ष में दो फसलें उगाने में समर्थ हो, ————— 10 एकड़,
- (ख) सुनिश्चित सिंचाई के अधीन भूमि की दशा में, जो एक वर्ष में एक फसल पैदा करने में समर्थ हो, ————— 15 एकड़,
- (ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों से भिन्न जिसमें फलोद्यान के अधीन भूमि सम्मिलित है ————— 30 एकड़,

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए जिला किन्नौर और लाहौल और स्पिति, जिला चम्बा की पांगी तहसील और उप-तहसील भरमौर, जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के बैजनाथ कानूनगो हल्के के छोटे भंगाल और बड़ा भंगाल क्षेत्र, और रोहड़ तहसील की डोडरा-क्वार पट्टवार हल्के के क्षेत्र और जिला शिमला की रामपुर तहसील के पन्द्रह-बीस परगनों के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र 70 एकड़ होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र, कुटुम्ब के प्रत्येक अतिरिक्त अवयस्क सदस्य के लिए उप-धारा (1) और (2) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र के पांचवें भाग के बराबर उस शर्त के अधीन बढ़ा दिया जायेगा, कि कुल अनुज्ञेय क्षेत्र उप-धारा (1) और (2) के अधीन कुटुम्ब के अनुज्ञेय क्षेत्र के दुगुने से अधिक नहीं होगा।

(4) व्यक्ति का प्रत्येक व्यस्क पुत्र एक पृथक इकाई माना जायेगा और वह इस शर्त के अधीन कि कुटुम्ब और पृथक इकाई को मिलाकर कुल भूमि उक्त उप-धाराओं के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र के दुगुने से अधिक नहीं होगी, उप-धारा (1) और (2) के अधीन कुटुम्ब के अनुज्ञेय क्षेत्र की सीमा तक भूमि का हकदार होगा:

परन्तु जहां पृथक इकाई के स्वामित्वाधीन कोई भूमि हो, वहां वह उसे युनिट के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र संगणित करने के लिए, हिसाब में ली जायेगी।

(5) यदि कोई व्यक्ति, इस धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) और उप-धारा (2) में उल्लिखित दो या अधिक वर्गों की भूमि धारण करता हो तो अनुज्ञेय क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा:—

- (i) इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि का एक एकड़, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित डेढ़ एकड़ और उप-धारा (i) क खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के सात एकड़ क बराबर गिना जायेगा;

- (ii) इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में भिन्न क्षेत्रों में, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि का एक एकड़ उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि का डेढ़ एकड़, और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के तीन एकड़ के बराबर गिना जायेगा :

परन्तु खण्ड (i), (ii) में विहित अनुपात के आधार पर अनुज्ञेय क्षेत्र को, तथा स्थिति, उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के वर्ग में परिवर्तित किया जायेगा, और इस प्रकार परिवर्तित कुल क्षेत्र, खण्ड (i) की दशा में 70 एकड़ और खण्ड (ii) की दशा में 30 एकड़ से अधिक नहीं होगा ।

(6) जहां व्यक्ति कुटुम्ब का सदस्य है वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि, कुटुम्ब के सभी सदस्य द्वारा धारित भूमि के साथ, अनुज्ञेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजन के लिए, हिसाब में ली जायेगी ।

5. इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

छूट ।

- (क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि,  
(ख) रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि सोसाइटियों की भूमि :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सोसाइटी के सदस्य का शेयर उसकी अन्य भूमि सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक नहीं है,

- (ग) भूमि बन्धक बैंकों, राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों और किन्हीं अन्य बैंकों की भूमि ।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए “किन्हीं” अन्य बैंकों से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में, यथापरिभाषित,

“तत्समान नया बैंक” कृषिक पुनर्वित्त निगम और कृषि उद्योग निगम, कृषिवित्त निगम लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कम्पनी और इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था है ;

- (घ) स्थानीय प्राधिकरणों की या उनमें निहित भूमि ;  
(ङ) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की भूमि ;  
(च) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित भू-दान यज्ञ बोर्ड के स्वामित्वाधीन भूमि ; और  
(छ) चाय सम्पदाएं ।

6. किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, चाहे भू-स्वामी या अभिधारी या कब्जा बन्धकदार के रूप में या अंशतः किसी एक हसियत में और अंशतः अन्य हसियत में, नियत दिन को या उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने का हकदार नहीं होगा ।

भूमि की अधिकतम सीमा ।

कतिपय  
अन्तरणों से  
अधिशेष  
क्षेत्र का  
प्रभावित न  
होना।

7. (1) संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अभिधारी द्वारा पैप्पू अभिवृत्ति और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 (1955 का 13) पंजाब भू-वृत्ति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का 10), या हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भू-सुधार अधिनियम, 1972 (1972 का 8) के अधीन अर्जित भूमि के सिवाय अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा, नियत दिन के पश्चात् सद्भावपूर्ण अन्तरण के सिवाय, अन्तरण, राज्य सरकार के अधिशेष क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार हकदार होती यदि ऐसा अन्तरण न किया जाता।

(2) कुलैक्टर यह अवधारित करेगा कि क्या अन्तरण सद्भावपूर्ण है या नहीं, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु अन्तरण को सद्भावपूर्ण सिद्ध करने का भार अन्तरिती पर होगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि का अन्तरण करता है, तो राज्य में निहित करने की दशा में, ऐसे अन्तरण के पश्चात् उसके फस बची भूमि को पहले हिसाब में लिया जाएगा और अन्तरित भूमि, को केवल निहित की जाने वाली भूमि को कमी को पूरा करने के लिए ही हिसाब में लिया जाएगा।

अनुज्ञेय क्षेत्र  
का चयन।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के या उसके पश्चात् किसी भी समय अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करेगा, अपनी सम्पूर्ण भूमि और पृथक इकाई को विहित प्ररूप और रीति में, विहित समय के भीतर कुलैक्टर को एक विवरणी देगा और उसमें कुल मिलाकर उस अनुज्ञेय क्षेत्र से, जिसे वह प्रतिधारित करना चाहता है, अनधिक भूमि के चयन के बारे में कथन करेगा।

परन्तु ऐसा व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् उस द्वारा किए गए भूमि के अन्तरण या अन्य निपटारे का विवरणी में उल्लेख करेगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन चयन की गई भूमि पूर्ण या आंशिक रूप में अभिधारियों के अधीन है, तो भू-स्वामी को, हिमाचल प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त अधिवृत्ति विधि में दिए गए आधारों के सिवाय अभिधारियों को उससे देखभाल करने का अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:—1. जहां व्यक्ति कुटुम्ब का सदस्य है, वहां वह अपनी घोषणा में उस द्वारा धारित भूमि का और कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, का भी विवरण सम्मिलित करेगा।

स्पष्टीकरण:—2. व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि के परिमाण की संगणना करने में अविभाजित कुटुम्ब, रजिस्ट्रीकृत कृषि स्काररी सोसाईटी या कम्पनी में ऐसे व्यक्ति के अंश को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अपने अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने में, भू-स्वामी, पृथक इकाई के लिए भी भूमि का चयन कर सकेगा।

परन्तु पृथक इकाई के लिए चयनित भूमि, नियत दिन को या उसके पश्चात् ऐसी इकाई के स्वामित्वाधीन भूमि जोड़ने के पश्चात् अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक नहीं होगी।

9. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे धारा 8 के अधीन विवरणी देना अपेक्षित है, जिसकी भूमि एक से अधिक पट्टवार हलकों में स्थित है, कुलैक्टर को उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि का ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विहित अवधि के अन्दर शपथ पत्र से समर्थित घोषणा, प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने में असफल रहता है तो कुलैक्टर ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन आदेश द्वारा कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

10. (1) धारा 8 के अधीन विवरणी में दी गई जानकारी या धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा जो ऐसे अभिकरण द्वारा सम्यक् रूप से, जो विहित किया जाए, सत्यापित की जाएगी, या धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन कुलैक्टर द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर कुलैक्टर अन्य विशिष्टियों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि के कुल क्षेत्र, विनिर्दिष्ट भूमि खण्ड जो कोई व्यक्ति अनुज्ञेय क्षेत्र या अधिकतम सोमा से छूट के तौर पर प्रति-धारित कर सकेगा और अधिशेष क्षेत्र को दर्शाते हुए विहित रीति में, प्रारूपित कथन तैयार करेगा।

(2) प्रारूपित कथन कुलैक्टर के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को विहित प्ररूप और रीति में तामील की जाएगी। तामील से तीस दिन के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप पर कुलैक्टर द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा और आक्षेपकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कुलैक्टर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(3) प्रारूपित कथन को, कुलैक्टर के आदेश या, यथास्थिति, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में पारित आदेश, यदि कोई हो, के निबंधनों पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

11. किसी व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र, उस तारीख को जिसको राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उसका कब्जा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, एतदपश्चात् उपबन्धित राशि के संदाय पर, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित कर किया गया समझा जाएगा और ऐसे क्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा द्वारा मान्यता प्राप्त सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, हक और हित (समाश्रित हित सहित, यदि कोई हों) निर्वापित हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, हक और हित किसी भी विल्लंगम से मुक्त रूप में राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे :

परन्तु जहां बन्धककर्ता के अनुज्ञेय क्षेत्र के भीतर कोई भूमि सकब्जा बन्धक की जाती है और बन्धकदार के अधिशेष क्षेत्र के भीतर आती हो, वहां केवल बन्धकदार अधिकार ही राज्य सरकार द्वारा अर्जित किए गए माने जाएंगे और वे इसमें निहित होंगे।

12. (1) कुलैक्टर, अधिशेष क्षेत्र हो जाने के पश्चात्, किसी भी समय लिखित रूप में आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र के कब्जाधारी व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह उस आदेश की तामील से दस दिन के भीतर उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि अधिशेष क्षेत्र का कब्जाधारी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश का, युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता

कतिपय भू-स्वामियों और अभिधारियों द्वारा शपथ पत्रों से समर्थित घोषणा प्रस्तुत की जाना।

कुलैक्टर की कथा प्रस्तुत करता।

अधिशेष क्षेत्र का राज्य सरकार में निहित होना।

अधिशेष क्षेत्र का कब्जा लेने की शक्ति।

है तो कुलैक्टर अधिशेष क्षेत्र का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐस बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो ।

भू-स्वामियों के हिस्सों को पृथक् करने की शक्ति ।

13. (1) जहां भू-स्वामी अन्य भू-स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से भूमि का स्वामित्व रखता है और ऐसी भूमि में या उसके भाग में, उसके हिस्से को अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया है या किया जाना है, ऐसा क्षेत्र घोषित करने के लिए सक्षम अधिकार या जहां ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी स्वप्रेरणा से, संक्षिप्त जांच करने और ऐसी भूमि में हित रखन वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्य भू-स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन भूमि या उसके भाग में से उसके हिस्से को पृथक् कर सकेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् और उसके उपयोग से पूर्व, उसकी भूमि चकबन्दी की प्रक्रिया के अधीन कर दी जाए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, चकबन्दी के पश्चात् उस द्वारा उपाप्त भूमि के क्षेत्र में से ऐसे व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र को पृथक् करने के लिए सक्षम होंगे ।

राशि के अवधारण और सदाय के लिए सिद्धांत ।

14. (1) जहां धारा 11 के अधीन कोई अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार में निहित हो गया हो, कुलैक्टर इसमें इसके पश्चात् उप-वर्णित निद्धान्तों के अनुसार उसके लिए संदेय राशि का विनिर्धारण करेगा अर्थात्—(1) दस एकड़ भूमि तक के लिए, भू-राजस्व का पचासवां गुणा (रेट और उपकरों सहित) । (2) दस एकड़ से अधिक और तीस एकड़ से कम भूमि के लिए, भू-राजस्व का पचहत्तर गुणा (रेट और उपकरों सहित), और (3) शेष भूमि के लिए, भू-राजस्व का पैंतालीस गुणा (रेट और उपकरों सहित) ऐसी भूमि के लिए देय होगा :

परन्तु यदि उस जोत या उसके भाग का, जो अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट है, भू-राजस्व के लिए निर्धारण नहीं किया गया है तो ऐसी भूमि पर भू-राजस्व सम्पदा में उसी प्रकार की भूमि पर और यदि सम्पदा में उपलब्ध न हो, तो यथास्थिति, संलग्न सम्पदा या सम्पदाओं पर निर्धारित किया गया अनुमानित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि भू-राजस्व के निर्धारण और राशि के अवधारण के लिए उजाड़ भूमि, बंजर भूमि मानी जायेगी ।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए कुलैक्टर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए राशि का कथन तैयार करेगा और विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों में राशि का प्रभाजन करेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र में बन्धकदार अधिकार, सरकार में निहित हो गया हो, वहां बन्धकदार को संदेय राशि, बन्धकदार को देय बन्धक राशि या इस धारा के अधीन संदेय राशि, जो भी कम हो, होगी ।

(4) जहां भूमि पर कोई भवन, संरचना, नलकूप या फसल है, वहां उसका स्वामी, भूमि के सम्बन्ध में संदेय राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सदन की जाने वाली राशि का हकदार होगा, जो ऐसे भवन, संरचना, नलकूप के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर होगी । भू-स्वामी अधिशेष क्षेत्र से खड़ी फसल के काटने का हकदार होगा ।

(5) राशि या तो एक मुश्त में या दस से अनधिक छ माही किस्तों में, विहित रीति में संदेय होगी ।

15. (1) अधिशेष क्षेत्र जो धारा 11 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गया है, राज्य सरकार के व्ययन पर होगा।

अधिशेष क्षेत्र का व्ययन।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसमें निहित अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के लिए आर्बंटन द्वारा स्कीम की विरचना कर सकेगी—

- (क) भूमिहीन व्यक्ति को या अन्य पात्र व्यक्ति को;
- (ख) घर के निर्माण के लिए विकलांग या घरहीन व्यक्ति को स्थान के आर्बंटन के लिए; और आर्बंटिती—

- (i) उसको आर्बंटित भूमि के लिए, भू-राजस्व के पचानवें गुणा की दर के अतिरिक्त उसके रेट और उपकर; और
- (ii) भवन, संरचना या नलकूप के लिए यदि कोई हो, ऐसे भवन संरचना या नलकूप के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय करेगा:

परन्तु यदि उस जोत या उसके भाग का जो अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट है, निर्धारण नहीं किया गया है तो ऐसी भूमि पर भू-राजस्व समझा जायेगा जो सम्पदा में उसी प्रकार की भूमि पर और यदि सम्पदा में उपलब्ध न हो तो, यथास्थिति, संलग्न सम्पदा या सम्पदाओं पर निर्धारित अनुमानित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि भू-राजस्व के निर्धारण और राशि के अवधारण के लिए उजाड़ बंजर भूमि मानी जायेगी।

(2-अ) उप-धारा (2) के अधीन अधिशेष भूमि का आर्बंटन करने के लिए भूमिहीन व्यक्तियों के बीच प्रथम अधिमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति क सदस्यों को दिया जायेगा।

• (3) राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (2) के अधीन विरचिन किसी स्कीम में उन निबंधनों और शर्तों का उपबन्ध किया जा सकेगा जिन पर अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट भूमि आर्बंटित की जायेगी।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में, परिवर्धन, संशोधन, फेर-फार या प्रतिसंहरण कर सकेगी।

15-अ. अधिनियम की धारा 15 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निहित भूमि के किसी क्षेत्र का उपयोग, राज्य के विकास के हित में किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे कर या सरकार के किसी विभाग को अन्तरण द्वारा कर सकेगी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है :

राज्य के विकास के लिए भूमि का उपयोग।

परन्तु जब किसी व्यक्ति द्वारा भूमि उस प्रयोजन के लिए प्रयोग न की जाए जिसके लिए यह पट्टे पर दी गई है, तो पट्टे का सभी विल्लंगमों से मुक्त पर्यावसान हो जायेगा और सरकार पट्टान्तरण परिसरों में पुनः प्रवेश करेगी, और पट्टे की राशि, यदि सरकार को संदत्त की हो, समपट्ट हो जायेगी और व्यक्ति उसमें किये गये किसी विकास और संनिर्माण की गई किसी इमारत के लिए, किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि के भावी अर्जन का वर्जन।

16. किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा, संविदा या क़ानून में किसी प्रतिभूल बात के होने हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से और उसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भू-स्वामी या अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार के रूप में, अन्तरण, विनियम, बन्धक, पट्टेदारी, करार या सैटलमेन्ट द्वारा कोई भी ऐसी भूमि अर्जित या धारण नहीं करेगा जो उसके स्वामित्वाधीन या उस द्वारा पहले धारित भूमि सहित या बिना, कुल मिला कर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाएं।

अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि का विरासत द्वारा या अन्यथा भावी अर्जन या ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप वृद्धि।

17. (1) धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति, चाहे भू-स्वामी या अभिधारी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका वह उत्तराधिकारी है, विरासत द्वारा या वसीयत या दान द्वारा, कोई भूमि अर्जित करता है, किसी व्यक्ति ने अन्तरण विनियम, बन्धक, पट्टेदारी, करार या सैटलमेन्ट द्वारा कोई भूमि अर्जित की है, या यदि, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति किसी अन्य रीति से कोई ऐसी भूमि अर्जित करता है जो, उसके स्वामित्वाधीन या उस द्वारा पहले धारित भूमि सहित या बिना, कुल मिला कर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाती है या कोई व्यक्ति, जिसकी भूमि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाती है तो वह, कुल्लैक्टर को, विहित अवधि के भीतर, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सम्पूर्ण भूमि की विशिष्टियां देते हुए और कुल मिलाकर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि का चयन करते हुए जिसे रखने का वह इच्छुक हो, विवरणी प्रस्तुत करेगा, और यदि ऐसे व्यक्ति की भूमि एक से अधिक पट्टवार हलकों में स्थित हो तो वह धारा 9 द्वारा अपेक्षित घोषणा भी प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि वह विहित अवधि के भीतर विवरणी देने और भूमि का चयन करने में असफल रहता है, तो कुल्लैक्टर, उसके सम्बन्ध में विवरणी में दर्शित की जाने के लिए अपेक्षित सूचना ऐसे अभिकरण द्वारा उपाप्त कर सकेगा जिसे वह उचित समझे और धारा 8 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके लिए भूमि का चयन करेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति घोषणा करने में असमर्थ रहता है, तो धारा 9 के उपबन्ध लागू होंगे।

(4) ऐसे व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि, धारा 15 के अधीन अधिशेष क्षेत्र के रूप में उपयोग किए जाने के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करे, राज्य सरकार के व्ययन पर होगी।

स्पष्टीकरण:--कुटुम्ब की दशा में विवरणी, कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य द्वारा और एकमात्र अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक द्वारा, दी जा सकेगी।

परन्तु कुल्लैक्टर, अधिशेष क्षेत्र का अवधारण करने से पूर्व, कुटुम्ब के समस्त सदस्यों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

अधिकारिता का वर्जन।

18. (1) किसी भी सिविल न्यायालय को,

(क) भूमि के अन्तरण के लिए संविदा के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष क्षेत्र पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करती है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए बाद को ग्रहण करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने, या

(ख) किसी मामले को निपटाने, विनिश्चित करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने, जिसका इस अधिनियम के अधीन निपटान, विनिश्चित या कार्यवाही किया जाना वित्तीय, आयुक्त, कुल्लैक्टर द्वारा अपेक्षित है, अधिकारिता नहीं होगी।



(2) इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुमरण में वित्तायुक्त, आयुक्त, कुलैक्टर कि कोई आदेश, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. इस अधिनियम के अधीन सदेय अन्य राशि की रकम और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

रकम और  
शास्ति की  
वसूली का  
ढंग।

20. (1) कुलैक्टर के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, विनिश्चय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगा :

अपील  
पुनर्विलोकन  
और पुनरी-  
क्षण।

परन्तु आयुक्त साठ दिन की उक्त अवधि के अत्रसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती देने के लिए वित्तायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका, दायर कर सकेगा और वित्तायुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

(3) पूर्वगामी उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तायुक्त किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के अभिलेख को, ऐसी कार्यवाहियों या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा, और उसके बारे में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

21. इस अध्याय के अधीन शांच करने वाले, अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाले किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित के बारे में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी.—

जांच करने  
वाले अधि-  
कारियों को  
सिविल  
न्यायालय  
की शक्तियों  
का प्राप्त  
होना।

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना ;

(ख) किसी भी व्यक्ति का उपस्थित कराया जाना और शपथ पर उसका परीक्षण ;

(ग) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना ;

(घ) कमीशन जारी किया जाना ;

और ऐसा प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 480 और 482 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय माना जाएगा।

22. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9 द्वारा अपेक्षित घोषणा देने में असफल रहता है या इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान ऐसी घोषणा या कथन करता है या ऐसी जानकारी देता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास करने का कारण है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

मिथ्या कथन  
करने के  
लिए शास्ति।

(2) कोई भी न्यायालय, उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सिवाय, कुलैक्टर द्वारा किए गए परिवाद के नहीं करेगा।

**प्रक्रिया** 23. इस अधिनियम के अधीन सभी जांचों और कार्यवाहियों में, कुलकर्टर और किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए।

**कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना।** 24. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

**इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।** 25. (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन या उनके अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के बारे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।  
(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों के फलस्वरूप कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान या सहन की गई या होने के लिए संभाव्य किसी क्षति के लिए, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**नियम बनाने की शक्ति।** 26. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधि-सूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।  
(2) उप-धारा (1) के अधीन किन्हीं नियमों को बनाने की शक्ति, नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुलमिला कर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो में या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या उससे ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में किसी परिवर्तन की अपेक्षा करती है या सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।** 27. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

**निरसन और व्यावृत्ति।** 28. (1) पंजाब सक्पोरटो आफ लैण्ड टेन्थोरस ऐक्ट, 1953 (1953 का 10) और पैन्थू टैनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चर लैण्ड्स ऐक्ट, 1955 (1955 का 13) और हिमाचल प्रदेश विशाल भू-सम्पदा समाप्ति और भू-सुधार अधिनियम, 1953 (1954 का 44) के उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हैं एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित अधिनियमितियों का निरसन, उनके पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निरसित अधिनियम या विधि के अधीन की गई किसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन या किए गए अन्तरण, जारी की गई अधिसूचना उद्घोषणा, आदेश, अनुदेश, या निदेश, प्रदत्त की गई कोई शक्तियां और प्राधिकार, अर्जित

अधिकार और उपगत उत्तरदायित्व, बनाए गए नियम, विनियम, प्ररूप या स्कीम, नियत की गई तारीख, समय और स्थान और अन्य बातों सहित, को गई कोई बात या को गई कार्रवाई—

(क) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों, यदि कोई हों, के अधीन की गई मानी जाएगी,

(ख) तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या को गई कार्रवाई द्वारा अन्यथा निदेशित या अधिकान्त नहीं कर दी जाती ;

(4) उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निपटार के लिए लम्बित वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों का निपटान, उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, मानों कि ये अधिनियम निरसित नहीं किए गए थे ।

(5) व्यावृत्ति.— जहां मूल अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन भूमि का कोई आबंटन, इस अधिनियम की धारा 2 और 3 द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत पाया जाए, वहां किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश; या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए ऐसे आबंटन को रद्द करना और इस प्रकार आबंटित भूमि का पुनः कब्जा लेना, विधिपूर्ण होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, प्रशुनगत भूमि के आबंटितों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, गारित नहीं किया जाएगा ।

में “दि हिमाचल प्रदेश सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट, 1972 (1973 का 19)” के राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता है और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने “दि हिमाचल प्रदेश सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट, 1972 (1973 का 19)” के, उपर्युक्त राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

